विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित आकाशवाणी के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर केन्द्र के साथ-साथ उनकी क्षमता और सिगनल रेंज को दर्शाने वाला ब्यौरा

वर्ष	राज्य	स्थल	शक्ति/क्षमता	रेंज (कि०मी० में)			
				पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	2	3	4	5	6	7	8
1992-93	असम	गुवाहाटी	50 कि.वा.शा.वे.		समग्र राज्य		
	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	50 कि.वा.शा.वे.		समग्र राज्य		
	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता "ख"	100 कि.वा.मी.वे.		205	220	220
1993-94	अरुणाचल प्रदेश	ईटा नगर	100 कि.वा.मी.वे.	65	125	135	35
	उड़ीसा	जैपौर	100 कि.वा.मी.वे.	80	80	80	80
		भवानी पटना	200 कि.वा.मी.वे.	135	135	135	135
	पश्चिमो बंगाल	कलकत्ता	50 कि.वा.शा.वे.		समग्र राज्य		
1994-95	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	50 कि.वा.शा.वे.		समग्र राज्य		
	हिमाचल प्रदेश	शिमला	50 कि.वा.शा.वे.		समग्र राज्य		
	कर्नाटक	बंगलौर	500 कि.वा.शा.वे. (4 अदद)		विदेशी सेवाओं हेतु		
	केरल	त्रिचूर	100 कि .वा.मी.वे.	90		65	125
		त्रिवेंद्रम	50 कि.वा.शा.वे.		समग्र राज्य		
	मध्य प्रदेश	भोपाल	50 कि.वा.शा.वे.		समग्र राज्य		
	महाराष्ट्र	बम्बई	50 कि.वा.शा.वे.		समग्र राज्य		
	मणिपुर	इम्फाल	50 कि.वा.शा.वे.		समग्र राज्य		
	राजस्थान	जयपुर	50 कि.वा.शा.वे.		समग्र राज्य		
	तमिलनाडु	तूतिकोरिन	200 कि.वा.मी.वे.		80	95	
		मद्रास	50 कि.वा.शा.वे.		समग्र राज्य		

*सीमा/समुद्र पार उपलब्ध कवरेज है।

आदिकालीन पर्यटन-स्थलों का विकास

*322. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात और मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे नये ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी मिली है, जिन्हें पर्यटन-स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है;

(ख) क्या सौराष्ट्र-कच्छ और खजुराहो क्षेत्र में आदिकाल के कुछ पुराने लक्ष तथा स्थल होने की सूचना प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकारों ने इन स्थानों को पर्यटन-स्थलों के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में सरकारी तौर पर कोई अध्ययन करवाया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) ऐतिहासिक स्थलों को शामिल करते हुए पर्यटक स्थलों का विकास और पहचान करना एक सतत् प्रक्रिया है जो अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य सरकार से नए ऐतिहासिक स्थलों और प्राचीन वृक्षों तथा आदिकाल के स्थलों के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

Publication of Booklet Titled "Highlights of Programmes, Policies & Implementation"

*323. SHRIMATI BASANTI SARMA:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the booklet published by the Ministry of Information and Broadcasting on 31st May, 1995, titled "Highlights of Programmes, Policies & Implementation" is available in regional languages;

(b) if not, whether it will be made available; and

(c) whether arrangements for its proper distribution will be made; and if so, by when?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI P.A. SANGMA): (a) and (b) The booklet titled "Highlights of Policies, Programmes and Implementation" has been brought out in English and [illegible] languages. Backgrounders/features based on this material have been issued by PIB Branch/Regional offices in other regional languages.

(c) The booklet has been supplied to eminent media persons and different media units of the Ministry for appropriate use in their publicity efforts.

Need for Reviewing the Policy of Seetting up Big Hydro Projects

*324. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report captioned "Temples of Modern India amidst controversy" appearing in the 'Times of India' of October 23, 1995, highlighting the need for a review of the whole policy of setting up big hydro projects; especially the projects presently in hand; and

(b) if so, the steps taken/being taken to cause a comprehensive review of the policy and the projects and the outcome thereof?

THE MINISTER OF POWER (SHRI N.K.P. SALVE): (a) and (b) The need to accord priority to the development of the hydro-electric power potential of the country for the optimum operation of the power system has been recognised by the Government. However, while clearing individul hydel projects for execution, due consideration is given to all relevant factors including environmental, rehabilitation and safety factors. No review of the present approach of the Government is comtemplated.